(ग) इसके परिणामस्वरूप दि० प० नि० को कितनी आय हुई और किस कम्पनी/एजेंसी ने दि० प० नि० को इस राशि का भुगतान किया और;

(घ) क्या विज्ञापन पेनल पर सांविधिक चेतावनी लिखी हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कृष्णा आर्ट स्टूडियो, सरदार हरफूल सिंह बिल्डिंग, क्लाक टावर, दिल्ली-110007 ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर गणेश सिन्धी बोड़ी के 11 बैक पेनलों के प्रदर्शन के लिए 10-3-81 को प्रार्थना पत्र दिया था। इसका ठेका 14-3-81 से 13-6-81 तक के लिए था।

(ग) कृष्णा आर्ट स्टूडियो ने दिल्ली परिवहन निगम को 4,908.75 रुपये दिए।

(घ) जी, हां।

Indian Defence Personnel in Pak Jails

623. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the External Affairs Minister during his visit to Pakistan in June, 1981 has discussed with the Government of Pakistan the issue of forty Indian Defence personnel who are in Pakistani jails; and

(b) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO: (a) and (b). Yes, Sir. The issue of Indian Defence personnel reported to be in Pakistani jails was once again taken up with the Government of Pakistan during the Foreign Minister's visit to Islamabad in June, 1981. The Government of Pakistan reiterated its position that there were no such Defence personnel in Pakistan.

घटिया औषधियों का निर्माण करने वाले बहु-राष्ट्रीय एककों के विरुद्ध कार्यवाही

624. **श्री कंवर भुवण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ऐसे बहुराष्ट्रीय औषध एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिनकी औषधियां पिछले एक साल के दौरान प्रयोगशाला-परिक्षणों में मानक स्तर से नीचे पायी गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण और बिक्री पर राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, और जिन औषधि यूनिटों के उत्पाद घटिया किस्म के पाये जाते है उनके विरुद्ध राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह कार्यवाही इस बात का ध्यान किये बिना की जाती है कि यह यूनिट बहुराष्ट्रीय या भारतीय क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र की एक बड़ी यूनिट है।

जब कभी भी राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों को घटिया किस्म की औषधियों की रिपोर्ट मिलती है तो बाजार से यथासंभव उस बैच की औषधियां वापस लेने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है। निर्माता द्वारा रखे गये रिकार्ड की भी यह देखने के लिए जांच की जाती है कि औषधि को रिलीज करने से पहले

उसका परीक्षण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है या नहीं । यदि इन जांचों के दौरान कोई त्रुटियां पाया जाता हैं तो पाई गई कमियों/त्रुटियों को देखते हुए तथा औषधि के निर्माण संबंध निर्धारित शर्त का पालन न करने पर किसी औषधि विशेष के लिए अथवा सम्पूर्ण निर्माण कार्य के लिए लाइसेंस को निलम्बित करने या अंशत: रद्द करने की कार्यवाही की जाती है । यदि निर्माता की औषधियां बार बार घटिया किस्म की पाई जाती हैं अथवा निर्माता की लापरवाही के कारण घटिया किस्म की औषधियां बनाई जाती हैं तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही का भी सहारा लिया जाता है ।

U.G.C. Plan for Development of Higher Education

625. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the details of the policy frame that has been evolved by the University Grants Commission for the development of higher education for the next 15 years; and

(b) by what time it will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) The policy frame adopted by the University Grants Commission in February 1978 for the development of higher education over the next ten to fifteen years envisages:—

(1) Adoption of measures which will reduce pressures on the university system through effective vocationalisation at the secondary stage, delinking jobs from degrees, changing recruitment policies which make a degree a minimum qualification for any good job;

(2) Restraint in the establishment of new institutions, which should not be set up (except in backward areas) unless the need is established on academic considerations and availability of resources;

(3) Planning the location of new institution very carefully and rationalising that of the existing ones;

(4) Selective admission to full-time institutions of higher education at the first degree and post-graduate levels on the basis of merit with reservation of at least half the seats for weaker sections;

(5) Provision of facilities to meet the full cost of education of talented but economically weaker students;

(6) Expansion of higher education through non-formal channels;

(7) Opening Secondary/Intermediate Board and University examinations to private candidates.

The major programmes suggested in the policy frame are restructuring of undergraduate courses, confinement of post graduate education and research to university departments, decentralisation of university administration, extension services to schools and to the community at large, improvement of standards both in terms of academic achievement as well as social commitment and contribution to national development, introduction of the regional languages as the medium of instruction, etc.

(b) The Commission has already circulated to all the universities detailed guidelines for formulation of specific programmes for implementation during the Sixth Plan period which take into account some of the major suggestions made in the policy frame. These suggestions have to be considered and implemented by the Universities themselves.